10. Madhya Pradesh	470
11. Maharashta	311
12. Manipur	22
13. Meghalaya	23
14. Nagaland	10
15. Punjab	65
16. Orissa	279
17. Rajasthan	102
18. Sikkim	2
19. Tamil Nadu	235
20. Tripura	38
21. Uttar Prades	1265
22. West Bengal	456
23. Andaman & Nicobar Islands	1
24. Arunachal Pradesh	33
25. Chandigarh	3
26. Dadra & Nagar Havali	1
27. Delhi	30
28. Goa, Daman & Diu	4
29. Lakshadweep	—
30. Mizoram	18
31. Pondicherry	4
Total	5093

कंट्रोल के कपड़े की मात्रा में वृद्धि करने का प्रस्ताव

4606. **श्री निहाल सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक सर्वेक्षण किया है जिसके अनुसार तीन महीनों में एक बार दिए जाने वाला कंट्रोल का कपड़ा गरीब लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी मात्रा में वृद्धि करने का है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में कंट्रोल के कपड़े के अन्तर्गत केवल धोतियां ही दी जा रही हैं जबकि जाड़े के दिनों में रंगीन मोटे कपड़े की मांग होती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) हालांकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन वैसे सरकार को कमियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, धोतियां, साड़ियां तथा लट्ठा सभी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिले-सिलाये सूती वस्त्रों का निर्यात

4607. **श्री निहाल सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों को सिले-सिलाए सूती वस्त्रों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) उन एजेंसियों के विवरण क्या हैं जिनको इस समय सरकार ने सिले-सिलाए सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी कर दिए हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसे मामले भी सरकार की जानकारी में लाए गए हैं जिनमें कुछ देशों ने लाखों रुपये मूल्य के सिले-सिलाए वस्त्रों का प्रेषित माल वापस कर दिया क्योंकि वे वस्त्र विनिर्देशन के अनुसार नहीं

थे और उसके परिणामस्वरूप उन देशों में भारत की साख में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन फर्मों और एजेंसियों का क्या विवरण है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) भारत से सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमरीका, ई० ई० सी०, कनाडा, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, जापान, सोवियत संघ तथा मध्य पूर्व के कुछ देशों को किया जाता रहा है।

(ख) कुछ कोटा देशों के सम्बन्ध में जहां सिले-सिलाये परिधानों के निर्यात मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों के अध्यधीन है, निर्यात प्रमाण-पत्र सरकार द्वारा निश्चित की गई कोटा वितरण नीति के आधार पर अपरेत निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी किए जा रहे हैं। अपरेत निर्यात संवर्धन परिषद आंकड़े मानिटर करने के लिए गैर कोटा देशों का सिले सिलाए परिधानों के निर्यातों के लिए गैर कोटा पृष्ठांकन भी जारी करती है।

(ग) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Foreign Loan

4608. SHRI PALAS BARMAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of foreign loan taken by India since Independence;

(b) the interest charged by the lending countries;

(c) the amount of money paid by India since Independence as interest only to other countries; and

(d) the amount of loan being sought from other countries and the amount of loan obtained during last year ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN) : (a) The amount of foreign loans taken by India since independence and upto 31st March, 1981 was Rs. 20192.9 crores.

(b) The interest charges vary from country to country and from agreement to agreement. However, these are in the range of 0.5% to 9.85% per annum.

(c) The amount of interest paid by India since independence to foreign countries is Rs. 3398.2 crores.

(d) Loan amounts are not sought as such from other countries. However, bilateral aid negotiations are held from time to time with other countries and the quantum of aid as well as the form i. e. loans and grants, in which it would be made available is known only after completion of these discussions. The total amount of loans received during 1980-81 was Rs. 1768.5 crores.

Hazard to Environment and Public Health Caused by Processing of Lead, Zinc and other Metals

4609. SHRI K. MALLANNA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the hazards to environment and public health caused by the processing of lead, zinc and other metals ; and